steps to see that these colleges also are equipped with science laboratories and theatres as the colleges of old times?

Shrimati Soundaram Ramachandran: I said that with the aid of UGC these summer institutes are run, even though the emphasis is on secondary education. But I accept that the scope of this question is wide. That is why I said that with US aid as well as UGC aid we are trying to improve the teaching of science in universities. But as university education is separate, I am not answering that part.

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या सरकार ने भारद्वाज मुनि कृत विमान शास्त्र और ऋग्वेद के अष्टम मंडल के वैमानिक सूक्त का अनुसंधान कराया है जिसमें लिखा है कि वायुयान बिना पैट्रोल के पारे से चलाया जा सकता है ? क्या यह चीज सोची गयी है ।

Mr. Deputy-Speaker: It does not arise.

Shri Kapur Singh: The question is most pertinent. Let her answer.

Mr. Deputy-Speaker: This is general education.

Shri Ram Sewak Yadav: She is willing to reply.

Dr. Chandrabhan Singh: If Government are not satisfied with the progress so far made in the field of scientific education, will they consider the desirability of reviving the Ministry of Scientific Education that was in existence before?

Shrimati Soundaram Ramachandran: That is not for me to say.

Administration of N.E.F.A.

\+

*630. Shri S. C. Samanta:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri M. L. Dwivedi:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it has been suggested by many people of Assam that Administration of NEFA should be done through Assam Government; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) Of late there has been on such suggestion.

(b) Does not arise.

Shri S. C. Samanta: Has the Assam Government experienced some difficulties because both are on the border?

Shri L. N. Mishra: No, no such suggestion has come from the Government of Assam recently.

Shri P. R. Chakraverti: Has Government any schemes of implementing the recommendations of Shri Pataskar also in NEFA when those recommendations are made?

Mr. Deputy-Speaker: Let them be known first. It is hypothetical.

Shri L. N. Mishra: Of course, his recommendations will be given all careful consideration.

श्री म० ला० द्विवेदी : यदि उप-मंत्री महोदय ने नेफा के प्रशासन को अलग बनाने सम्बन्धी कागजात को देखा होगा तो उनको विदित होगा कि नेफा के प्रशासन को अलग करने का उद्देश्य यह था कि उसका संतुलित विकास किया जाए और ज्यों ज्यों उसका विकास होता जाएगा वैसे वैसे उसे असम के शासन में मिला दिया जाएगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अपने उस निर्णय में कोई परिवर्तन कर दिया है, उस विचार को बदल दिया है, यदि नहीं तो नेफा के प्रशासन को असम के साथ मिलाने का प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता ?

श्री ल० ना० मिश्र : इस वक्त नेफ़ा आसाम से अलग है और गृह मंत्रालय के अधीन है । वहां के गवर्नर राष्ट्रपति के एजेंट की हैसियत से काम करते है । वह अपने एडवाइजर और चार पांच सेक्रेटरीज की सहायता से वहां का प्रशासन चलाते हैं । जहां

तक वहां के विकास का सवाल है, हम चाहते हैं कि उस क्षेत्र का विकास तेजी से हो। हम वहां की शासन प्रणाली में भी परिवर्तन लाना चाहते हैं और हमने लाए भी हैं। मैं माननीय सदस्य का ध्यान एरिंग कमेटी की रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसने यह सुझाव दिया है कि वहां पर कुछ परिवर्तन लाये जायें। खास तौर से उसने बताया है कि वहां पर अंचल समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद् आदि की शुरूआत की जाये। हम वह करना चाहते हैं।

Shri P. C. Borooah: May I know whether a suggestion was made to the Government recently to establish a common service cadre for NEFA and Assam, and if so, may I know the reaction of the Government in this regard?

Shri L. N. Mishra: We have no such proposal. We want to have the Union Territories Cadre for NEFA also, but that is under the examination of the Law Ministry.

Shri D. C. Sharma: May I know how much money was allotted for NEFA in the Third Plan, and whether the performance of NEFA has been according to schedule up to this time in this respect?

Shri L. N. Mishra: I require notice for this question.

श्री भागवत झा आजाद : इतने वर्षों से इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। अभी माननीय उपमंत्री ने कहा है कि नेफा में पंचायती राज लागू करने का विचार किया जा रहा है। क्या इन बातों को सामने रखते हुए हम यह सोचें कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि नेफ़ा को आसाम राज्य के साथ अन्तर्हित कर दिया जाये ?

श्री ल० ना० मिश्र : जहां तक नेफ़ा को आसाम में मिलाने का प्रश्न है, हम को यह सोचना होगा कि इस बारे में नेफ़ा के निवासियों की क्या प्रतिक्रिया है। उस को मद्देनजर रखते हुए ही हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं। जहां तक वहां के शासन को देश के बाकी शासन के स्तर पर लाने का सम्बन्ध है, वह हम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने "पोलिटिकल आफ़िसर" का नाम "डिपुटी कमिश्नर" रखा है और "फ्रंटियर डिविज़न" का नाम "जिला" रखा है। ये सब काम हम कर रहे हैं। आसाम में मिलाने से पहले हम को यह सोचना होगा कि नेफ़ा के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सीमावर्ती राज्य, आसाम, के मुट्ठी भर लोगों को इस समय तीन भागों में विभक्त किया हुआ है : आसाम, नेफ़ा और नागालैंड। इससे पृथकत्व की प्रवृत्ति का उदय हुआ है और इसी कारण मिजो पहाड़ियों के लोग पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं। क्या सरकार इस प्रकार की प्रवृत्तियों का दमन करने के लिये अब नहीं तो आगे चल कर इन सब क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने का निश्चय करेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन वक्त मौजूं नहीं है।

Shri Hem Barua: May I know if it is a fact that Government proposes to give representation to the NEFA people in the Assam Legislative Assembly so as to enable them to experience some of the pangs and pleasures of our parliamentary functioning, as also to implement the constitutional provision that stimulates the ultimate integration of NEFA with Assam?

Shri L. N. Mishra: It is a suggestion for action. We will try to look into that.

Shri Hem Barua: This is not a suggestion. I put a specific question whether the Government proposes to give representation to the NEFA people in the Assam Legislative Assembly so as to enable them to ex-

perience some of the pangs and pleasures of our parliamentary functioning as also to implement the constitutional provision that stimulates the ultimate integration of NEFA with Assam.

Shri L. N. Mishra: I still hold that it is a suggestion for action. We have not taken a decision yet in this matter.

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वह नेफ़ा में पंचायती राज की स्थापना की व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार कब तक इसको प्रारम्भ कर देगी, जिससे वहां के के लोग सारी कार्य पद्धति को समझ सकें और आसाम में मिलने की तैयारी कर सक।

श्री ल० ना० मिश्र : यह काम नेफ़ा को आसाम में मिलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं यह बात साफ़ कर देना चाहता हूं। हम वहां के लोगों को इस भ्रम में न डाल कि हम उनकी मर्जी के खिलाफ़ नको आसाम में मिलाना चाहते हैं। न पहले कभी हमारी यह ख़्वाहिश थी और न आज है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने भी इस बात को साफ़ कर दिया था कि नेफ़ा के लोगों की मर्जी के खिलाफ़ उनको कहीं नहीं डाला जायेगा। वहां पर ग्राम पंचायतों की स्थापना हम नेफ़ा को आसाम में मिलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम वह इसलिए कर रहे हैं, ताकि वहां के शासन में वहां के लोगों का अधिकार हो।

श्री तुलशी दास जाधव : नेफ़ा को आसाम से बाहर रखने से वहां के लोगों में जुदापन की भावना पैदा होती है। इसलिए उसको आसाम के साथ क्यों नहीं मिलाया जाता है, ताकि उनमें इन्टेग्रेशन की भावना पैदा हो।

श्री ल० ना० मिश्र : यही बात श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने भी कही है। इन्टेग्रेशन की बात अच्छी है, लेकिन सवाल यह है कि वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। धीरे धीरे हम दूसरे क्षेत्रों के साथ को-आर्डिनेशन का प्रोग्राम बना रहे हैं। हमारे विद्यार्थी वहां आते जाते हैं। एक मैडिकल कालेज के विद्यार्थियों की टीम वहां गई थी। वे वहां के लोगों से मिले। इस प्रकार आपस में मिलना जुलना बढ़ रहा है। यह काम धीरे धीरे हो सकता है, लादने से नहीं हो सकता है।

New Universities

+
*631. Shri Surendra Pal Singh:
Shrimati Tarkeshwari Sinha:
Shri Bagri:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the University Grants Commission and the Planning Commission have unanimously recommended that no new Universities should be established in the country during the Fourth Plan period;

(b) if so, the main basis for such a recommendation; and

(c) the State Governments' reactions to this proposal?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The University Grants Commission has not made any formal recommendation to the effect that no new universities should be established during the Fourth Plan. However, it has expressed the opinion that before any new university is established by a State Government, a perspective plan of 5—10 years may be prepared in consultation with the Commission, keeping in view the requirements of the area and the facilities available. But the Planning Commission has suggested to the State Governments in the context of formulation of proposals for the